मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2021-23 /R.N.I. No. 2022007062

मारुति मज़दूरों के साथ अदालत में घोर अन्याय हुआ है 2
नगर निगम के जेई को अतिक्रमण में दिखीं सिर्फ तीन दुकानें 4
2023 का जून 1974 का 5 जून बन पाएगा कि नहीं ? 5
सावरकर पर फिल्म का टीज़र: झूठ का पुलिंदा 6
मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी कोर्स होंगे शुरू 8

वर्ष 37 | अंक 45 | फरीदाबाद | 11-17 जून 2023 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

खट्टर सरकार मारेगी और रोने भी नहीं देगी

भयभीत किशोर ने की आत्महत्या, विरोध में कैंडलमार्च भी रोका

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) संघी भाजपाई सरकार अपने प्रत्येक जनविरोधी कुकर्म को देशहित में बताती है। विरोध करने वाले प्रत्येक नागरिक को देशद्रोही का तमगा देने में जरा भी गुरेज नहीं करती। मामला चाहे पहलवान बेटियों का हो या रिवाजपुर वासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन का, सरकार को फूटी आंख नहीं सुहाता।

खट्टर सरकार द्वारा गांव रिवाजपुर में कूड़ा घर बनाने के विरोध में उतरे आस-पास के 16 गांवों के निवासियों ने जब सरकारी षडयंत्र को विफल कर दिया तो ओछा हथकंडा अपनाते हुए, वर्षों से बसी ग्रामीण कॉलोनियों के घरों को तोड़ने के नोटिस जारी कर दिये, कुछ को तोड़ भी दिया। घर तोड़े जाने की दहशत से अजय नामक किशोर ने 31 मई को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

इस आत्महत्या से सारे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा शोक प्रदर्शन करना तो बनता ही था; लिहाजा ग्रामीणों ने रविवार 4 जून को इस उपलक्ष्य में कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया। सरकार के क्षेत्रीय प्रतिनिधि होने के नाते, प्रदर्शनकारियों ने सांसद एवं केन्द्रीयमंत्री कृष्णपाल गूजर के आवास तक जाने का निर्णय किया था। परन्तु सत्ता के अहंकार एवं नशे में डूबी इस सरकार को भला यह प्रदर्शन कैसे सुहा सकता था? लिहाजा कृष्णपाल गूजर के इशारे पर रिवाजपुर क्षेत्र को इस तरह से पुलिस छावनी में बदल दिया गया कि कोई भी प्रदर्शकारी गांव से बाहर न निकल सके। इसी को तो कहते हैं कि जबरा मारे भी और रोने भी न दे, यानी सरकार मारती भी है और रोने भी नहीं देती।

इस पर टिप्पणी करते हुए ग्रामीणों का कहना है कि आज तो कृष्णपाल गूजर ने उन्हें, उनके गांव में ही घेर दिया; कल जब वह वोट लेने आयेगा तब वे देखेंगे कि वह गांव में कैसे घुसता है? इसे लेकर ग्रामीणों

ने एक यज्ञ का आयोजन भी किया था जिसमें कृष्णपाल का विरोध करने की शपथ ली गई। गौरतलब है कि कृष्णपाल गूजर बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि लोगों ने उन्हें वोट थोड़े ही दिया है, वोट तो मोदीजी को दिया था। इतना ही नहीं, अब तो वे यह कहते भी सुने जा रहे हैं कि उन्हें किसी का वोट चाहिये ही नहीं। जाहिर है कि उनकी वही पुरानी मंशा है कि वोट तो मोदीजी के नाम पर ही मिलेगा। वैसे उन्हें यह भी आशंका है कि उनके प्रति जनाक्रोश को देखते हुए मोदीजी उनकी जगह कोई नया 'साफ-सुथरा' उम्मीदवार न खड़ा करें।

प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे पारस भारद्वाज, गांव लालपुर से ललित चौहान, गांव महावतपुर से सरपंच रवि चौहान, कंवर सिंह चौहान, गांव ददसिया से कुलदीप त्यागी, गांव रिवाजपुर से विजयपाल, जसराम, विकास, राजवीर, अभिषेक चौहान, बिंदु, संगीता, सविता, रोहतास, कपिल, बाबा रामकेवल इत्यादि सैंकड़ों लोगों ने घोषित किया कि वे किसी भी हाल में अपने यहां दूसरा बंधवाड़ी नहीं बनने देंगे। इसके लिये वे आखिरी दम तक संघर्ष करते रहेंगे तथा अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार को उचित सबक सिखाएंगे।

अधिकारियों का खास है ठेकेदार इसलिए धरती पर कम और कागजों में ज्यादा लगे पौधे

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) लूट कमाई में मस्त नगर निगम के अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण के नाम पर ठेकेदार से मिलीभगत कर 49 लाख रुपये की हेराफेरी कर डाली। यह आरोप हम नहीं बल्कि ओल्ड फरीदाबाद के भाजपा विधायक नरेंद्र गुप्ता ने लगाए। दरअसल वह अपनी विधानसभा क्षेत्र में ग्रीन बेल्टों का निरीक्षण करने निकले थे लेकिन हरे भरे की जगह कई सौ मीटर दूरी पर एक पौधा दिखाई दिया। निगम अधिकारी ठेकेदार का बचाव करते नजर आए।

शहर की सड़कों के सेंट्रल वर्ज और ग्रीन बेल्टों को हरा भरा रखने, उनमें लगाए गए पौधों की रक्षा के लिए ग्रिल लगाने के लिए नगर निगम के बागवानी विभाग ने 2021-22 में 49 लाख रुपये का टेंडर जारी किया था। इसके तहत ठेकेदार को ओल्ड फरीदाबाद जोन की सड़कों के सेंट्रल वर्ज और ग्रीन बेल्ट में 25 हजार पौधे लगाने थे, ग्रीन बेल्ट में घास लगानी थी। इन पौधों और घास के तीन महीने तक रखरखाव और उनके जीवित रहने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की थी। ग्रिल भी लगाने थे।

यह टेंडर रोहतक की यादव कोऑपरेटिव नाम की संस्था को मिला। ठेकेदार को यह 25,000 पौधे, ग्रिल और घास नवंबर 2022 से पहले लगा देने थे। न तो कहीं पौधे लगाए गए न घास रोपी गई और ग्रिल का तो कोई अता-पता भी नहीं। हाल ही में भाजपा विधायक नरेंद्र गुप्ता ने इलाके का दौरा किया तो यह भेद खुला।

बागवानी के जेई ने ठेकेदार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए उन्हें बताया कि पंद्रह हजार पौधे लगाए जा चुके हैं। विधायक को खुश करने के लिए बताया कि दस हजार पौधे नर्सरी में रखे हैं जहां आपने बताए हैं वहीं लगवाए जाएंगे। बताया कि पूरे पौधे नहीं लगाए जाने के कारण ठेका कंपनी के भुगतान में दस प्रतिशत काटने की संस्तुति की गई है, इसकी आड़ में जेई साहब यह छुपा गए कि ठेकेदार ने ग्रिल और घास सौ प्रतिशत नहीं लगाई है। हालांकि कहीं पंद्रह

अपनी सरकार को रोते विधायक नरेन्द्र गुप्ता

हजार पौधे नजर नहीं आए लेकिन उनके दावे को कुछ देर के लिए सभी भी मान लिया जाए तो ठेकेदार ने चालीस प्रतिशत पौधे भी नहीं लगाए हैं। ऐसे में यदि उसके दस प्रतिशत काट कर नब्बे फीसदी का भुगतान कर दिया गया तो भी वह फायदे में रहेगा। आला अधिकारी तो ठेकेदार के पक्ष में यहां तक कह गए कि वह तो पच्चीस हजार से कहीं अधिक पौधे लगा चुका है लेकिन पौधों का जीवनकाल ही तीन माह था। तीन माह बाद वह मर गए लेकिन हमने ठेकेदार से कह कर उन्हें दोबारा लगवाया। अधिकारी कहते हैं कि जेई साहब विधायक जी को ठीक से बता नहीं सके कि ठेकेदार तो अपना काम कर चुका है, ऐसे में उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

समझा जा सकता है कि अधिकारी पर्यावरण और आम जनता के हित में नहीं बल्कि ठेकेदार के हित में काम कर रहे हैं क्योंकि वही तो उन्हें ऊपरी कमाई कराते हैं।

सवाल तो विधायक नरेंद्र गुप्ता पर भी बनता है। नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदार, पेड़ लगाने के नाम पर जनता के धन को डकार रहे हैं तो आप सत्तारूढ़ दल में बैठ कर क्या कर रहे हैं। जनता ने आपको अपने अधिकारों की रक्षा का दायित्व दिया है लेकिन आप मात्र एक तमाशबीन की भूमिका से अधिक कुछ नहीं निभा रहे।